अमित शाह ने अलवर से 6453 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी

अलवर/जयपुर, 16 अगस्त। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को सशक्त करना होगा। आज इन वर्गों के उत्थान की अवधारणा 'ज्ञान' अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण का संकल्प पूरा हो रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री रविवार को अलवर के विजयनगर ग्राउंड में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास

- **केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ये लोकार्पण व शिलान्यास केवल ईंट और पत्थर के प्रकल्प नहीं, बल्कि अलवर के मजबूत व उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं।**

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अलवर के विजयनगर ग्राउंड में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज किसानों को किसान सम्मान निधि, महिलाओं और पशुपालकों के लिए डेयरी की सुविधाएं तथा युवाओं को नौकरी की सौगात दी गई है। साथ ही, 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। भविष्य में इसकी क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इससे पशुपालक परिवारों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि 274 करोड़ रुपये की लागत के सरस डेयरी के चार और प्लांट भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। इसके साथ-साथ फलोदी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में चार नए केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शुरुआत भी आज हो रही है। इनसे किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।

इस दौरान केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के तहत 66 लाख 74 हजार से अधिक किसानों के खातों में करीब 667 करोड़ रुपए एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने नए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गठन के साथ प्रदेश के 17 जिलों में 6 हजार 453 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 17 जिलों को 6 हजार 453 करोड़ रुपये के 954 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करना है।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में दशकों से लंबित यमुना जल समझौते को मुकाम तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए राजस्थान हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की सौगात से अलवर विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वे केवल ईंट और पत्थर के बने हुए प्रकल्प नहीं हैं, बल्कि अलवर के मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जवाहर सिंह बेढ म, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, सांसद मदन राठौड़, विधायकगण, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन डॉ. मीनेश शाह सहित सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुझे गर्व है कि मैं "दिमागी नक्सली" हूँ- चिदंबरम

नई दिल्ली, 16 अगस्त। कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने कहा, कि उन्हें गर्व है कि वे "दिमागी नक्सल" हैं। चिदंबरम, प्रधानमंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से की गई उस अपील पर कटाक्ष कर रहे थे जिसमें उन्होंने "दिमागी

- **कांग्रेस नेता पी. चिदबरम ने प्रधानमंत्री की "दिमागी नक्सलियों" की अपील पर कटाक्ष किया।**

नक्सलियों" से सावधान रहने को कहा था। उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रधानमंत्री ने लालकिले से कहा था कि दशकों तक सत्ता में रहे ये दिमागी नक्सली अब मौके की तलाश में हैं और अराजकता के नए रास्ते खोज रहे हैं। ये लोग समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति-भांति के दांव चल रहे हैं।

अलगाववादियों व माओवादियों को "दिमागी नक्सल" कहा, विपक्षी नेताओं को नहीं- रिजिजू

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए "दिमागी नक्सल" शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसे लोगों को अलग-थलग करने की जरूरत बताई थी।**

नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल को लेकर रविवार को स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को 'दिमागी नक्सल' नहीं कहा है, बल्कि यह शब्द माओवादियों, अलगाववादियों और भारत को तोड़ने की विचारधारा रखने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के बयान की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि माओवाद का समर्थन करने, भारतीय संविधान को अस्वीकार करने, अलगाववादियों के साथ खड़े होने और अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले लोगों के अलावा पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की कोशिश करने वालों को 'दिमागी नक्सल' कहा गया है।

अपने पोस्ट के साथ रिजिजू ने शर्जील इमाम के एक पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की बात कही गई थी।

ज्ञातव्य है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ऐसे लोगों को अलग-थलग करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री का इशारा सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले विपक्षी दलों और नेताओं की ओर था।

रिजिजू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को 'दिमागी नक्सल' नहीं कहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, संविधान को अस्वीकार करते हैं या देश की एकता और अखंडता के खिलाफ अलगाववादी विचार रखते हैं।

कांग्रेस की सफाई: सोनिया खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं

कांग्रेस ने कहा कि उनके कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाया गया

नई दिल्ली, 16 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में कथित तौर पर पूरा वंदे मातरम् ना गाने को लेकर राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर पूरा गीत ना गाने पर आपत्ति जताई है। जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि खड़गे काफी समय खड़े हुए थे।

कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम् पूरी तरह से बजने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई और सोनिया गांधी सिर्फ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, जो कुछ समय से खड़े हुए थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि शनिवार के कार्यक्रम में गीत का पूरा संस्करण गाया गया था। जयराम रमेश ने गीत के साथ पार्टी के ऐतिहासिक जुड़ाव का हवाला देते हुए कलकत्ता में 1937 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का जिक्र किया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे। रमेश ने बताया, 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई

- **कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर 1937 में वंदे मातरम् के प्रारंभिक श्लोक गाने का फैसला लिया गया था।**

पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर उन्होंने फैसला लिया कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के प्रारंभिक श्लोक गाए जाएंगे।

वंदे मातरम् विवाद पर कांग्रेस 24 घंटे में माफी मांगे- भाजपा

नई दिल्ली, 16 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पाठ के कथित विरोध को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस से इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

भाजपा मुख्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का विरोध केवल 'दिमागी नक्सल' विचारधारा से प्रभावित लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पांच सवाल भी पूछे। भंडारी ने वंदे मातरम का कथित तौर पर अपमान किए जाने को लेकर कांग्रेस से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस विचारधारा के राजनीतिक संरक्षक हैं। उन्होंने एक ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि इसमें राहुल गांधी के वंदे मातरम नहीं गाने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस सरकार ने भी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पाठ नहीं किया।

बाढ़ में लापता हुए सेना के पाँच जवानों की कोई खबर नहीं

ईटानगर, 16 अगस्त। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण दिबांग वैली जिले में लापता हुए सेना के पांच जवानों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। उनकी खोज का काम जारी है। हाल ही में अचानक आयी बाढ़ में सेना के पांच जवान लापता हो गए थे, जिसमें से दो का बचा लिया गया था।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि खोज और

- **अरूणाचल में भारी वर्षा से आर्मी कैंप से दो शैल्टर शुक्रवार को बह गए थे**

बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन अभी तक लापता हुए पांच जवानों की कोई खबर नही मिली है। अधिकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब दिबांग वैली जिले में अचानक आई बाढ़ में सेना के दो शेल्टर (आश्रय स्थल) बह गए थे। मिपी सर्कल से लगभग 25 किलोमीटर दूर पासु पानी में अचानक आई बाढ़ से यह हादसा हुआ था। इसके कारण आसपास के इलाके में पानी भर गया, जिससे सेना के साथ आम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई है। बाढ़ में पासु पानी आर्मी कैंप में 5वीं ग्रेनेडियर्स के दो शेल्टर बह गए थे। इसमें सेना के सात जवान भी थे, जिसमें से दो को बचा लिया गया, जबकि पांच अभी भी लापता हैं।

शेख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले कुछ हफ्तों से संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की एक प्रेस वार्ता ने भी रहमान की यात्रा को प्रभावित किया है। करीम ने कहा, "हमारा मानना है कि इस उच्च स्तरीय दौरे के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाना आवश्यक है।"

बांग्लादेश ने भारत सरकार से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए शेख हसीना और अन्य भगोड़ा अपराधियों को जल्द से जल्द सौंपने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, बांग्लादेश ने राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को भी बांग्लादेश के हवाले करने की मांग की है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा शेख हसीना को दोषी ठहराए जाने के बावजूद नई दिल्ली में उनकी खुली प्रेस वार्ता को लेकर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है।

बांग्लादेश का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंधों का माहौल प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना द्वारा की गई प्रेस वार्ता का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

प.बंगाल के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव रामपुरहाट शहर स्थित उनके घर से लगे पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों ने सबसे पहले पार्टी कार्यालय की खिड़की से आशीष बंद्योपाध्याय को फंदे से लटका देखा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को आशीष बंद्योपाध्याय से अनेक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में रामपुरहाट से भाजपा के ध्रुव साहा के हाथों चुनाव हारने के बाद आशीष बंद्योपाध्याय सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर हो गए थे। घटनास्थल पर मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी के सभी गलत कामों को हमेशा स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया है। सुसाइड नोट में उन्होंने किसी रेत के टेंडर का जिक्र किया है। आशीष ने लिखा कि टीआरडीए (तारापीठ-रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी) के टेंडर, प्लान पास करने, एनओसी और चेक से जुड़े मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

आशीष ने लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने राजनीति में आने पर अफसोस जताया।

'जो वंदे मातरम् ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर और भी अधिक लागू होती है।" इसी वजह से देश को "मदर इंडिया" कहा जाता है। कुन्नुम्मल ने कहा, "इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वंदे मातरम् कहते हैं। जो लोग वंदे मातरम् कहने का विरोध करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी मां कौन है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनकी मां कौन है, जो लोग समझते हैं कि मां क्या होती है, वे हमेशा वंदे मातरम् कहेंगे। इसे इसी तरह कहा जाना चाहिए।" छात्र संगठनों एसएफआई और केएसयू ने आरोप लगाया है कि कुन्नुम्मल केरल विश्वविद्यालय में आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल द्वारा कुन्नुम्मल को कुलपति नियुक्त किए जाने पर एलडीएफ और यूडीएफ ने सवाल उठाए हैं। दोनों गठबंधनों ने आरोप लगाया है कि यह केरल की शिक्षा व्यवस्था को "भगवा रंग" देने की कोशिश है।

रांची में आंदोलनकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।

आंदोलन में अब छात्रों के साथ उनके परिजन भी जुड़ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक किया जाएगा। वहीं, छात्रों से बातचीत करने के लिए एक बार फिर राज्य सरकार तैयार हो गई है।

एसडीएम के मुताबिक, सोमवार, 17 अगस्त को छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों को विधि सलाहकार के साथ दोपहर दो बजे बातचीत के लिए बुलाया है।

देश के युवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्माण में युवाओं से आगे आने का आव्हान करते हुए कहा कि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं जीना है। दुनिया में कई चीजें सस्ती और आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन देश का वास्तविक सामर्थ्य अपनी क्षमताओं के निर्माण से तैयार होता है। इसलिए भारत को अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत करना होगा।

कड़ी होड़ लगी है, यू.एन. के महासचिव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में उनका अनुभव उन देशों को पसंद आ सकता है, जो असमानता, कर्ज और वैश्विक आर्थिक सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने वाले नेता की तलाश में हैं। उनकी बढ़त उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाती है, हालांकि सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य का समर्थन उनके भविष्य का फैसला कर सकता है।

गुयाना की पूर्व विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक रोड्रिग्स-बिरकेट पहले मतदान में दूसरे स्थान पर रहीं। उनकी उम्मीदवारी में कैरिब्रियन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, बहुपक्षीय कूटनीति का अनुभव और ऊर्जा उत्पादन करने वाले एक छोटे देश का नज़रिया शामिल है।

अर्जेंटीना के राजनयिक ग्रॉसी, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के प्रमुख हैं, पुरुष उम्मीदवारों में शायद सबसे चर्चित नाम हैं। परमाणु सुरक्षा से जुड़े मामले, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संकट प्रबंधन में मजबूत दावेदार बनाते हैं। माना जाता है कि उन्हें वॉशिंगटन का समर्थन हासिल है, हालांकि दूसरी बड़ी शक्तियां उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर सकती हैं।

चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त मीशैल बाशले अपने साथ राजनीतिक कद और सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों का व्यापक अनुभव लेकर आती हैं। उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड उनके लिए फायदे और नुकसान दोनों का कारण बन सकता है, क्योंकि चीन, अमेरिका और रूस उम्मीदवारों की बारीकी से जाँच-परख करते हैं।

इक्वाडोर की पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्व अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा एक और अनुभवी लैटिन अमेरिकी राजनयिक हैं। वह बहुपक्षीय व्यवस्था, लैंगिक समानता और विकासशील देशों की अधिक मजबूत भूमिका पर जोर देती हैं। सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी साल सबसे प्रमुख अफ्रीकी उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका अनुभव उन्हें राजनीतिक मजबूती देता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक प्रतिनिधित्व देने की मांग को भी जीवित रखता है।

दौड़ में देर से शामिल होने वाले उम्मीदवार युगांडा के ओलारा ओटुन्नू हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप-महासचिव और बच्चों तथा सशस्त्र संघर्ष से जुड़े मामलों के विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्थान में उनके अनुभव के कारण, यदि प्रमुख उम्मीदवारों के बीच गतिरोध पैदा होता है तो वह "समझौते वाले उम्मीदवार" के तौर पर आगे आ सकते हैं।

हालांकि, अंततः इस चुनाव का फैसला लोकप्रियता से ज्यादा भू-राजनीति से होगा। पंद्रह सदस्यीय सुरक्षा परिषद को एक उम्मीदवार की सिफारिश करनी होगी। इसके पांच स्थायी सदस्य-अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस-वीटो का अधिकार रखते हैं। जनरल असैंबली द्वारा सैक्रेटरी जनरल के तौर पर औपचारिक नियुक्ति से पहले किसी उम्मीदवार को कम से कम नौ वोट हासिल करने होंगे और किसी स्थायी सदस्य का वीटो नहीं होना चाहिए। इसलिए यह मुकाबला न केवल व्यक्तित्वों की परीक्षा बन जाता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की भविष्य की दिशा की परीक्षा भी बन जाता है। वॉशिंगटन ऐसा नेता चाहता है, जो व्यापक वित्तीय और ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, जबकि बीजिंग ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति सहानुभूति रखता हो।

जीतने वाले के लिए यह पद पुरस्कार कम और एक कठिन जिम्मेदारी अधिक होगा। उसे ऐसे संगठन को फिर से मजबूत करने का काम करना होगा, जिसकी विश्वसनीयता, वित्तीय स्थिति और कार्रवाई करने की क्षमता पर अभूतपूर्व दबाव है।

'हाई कोर्ट "आर्बिट्रेटर" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आखिरकार 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया। परन्तु इस अवधि में भी जब सुनवाई पूर्ण नहीं हो पा रही थी तो समय अवधि पुनः बढ़ ाने के लिए एच सी एल ने कमर्शियल कोर्ट में गुहार की और आखिरकार कमर्शियल कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 तक समय अवधि बढ़ा दी। इस आदेश के खिलाफ सभी संबंधित विद्युत वितरण निगम हाई कोर्ट पहुंची थी जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रिब्यूनल को 1 महीने का समय दिया था सुनवाई का निस्तारण करने और उसके अतिरिक्त 15 दिन का समय फैसला सुनने के लिए। हालांकि अदालत ने माना था कि मामला बेहद ही पेचीदा है और 33 अलग अलग तरह के दावे है, अलग अलग अनुबन्धनो से सम्बन्धित जो अलग अलग शहरों में क्रियान्वित किए जाने थे इसलिए अदालत ने कमर्शियल कोर्ट के फैसले को निरस्त नहीं किया परन्तु सुनवाई की समय अवधि को घटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष याचिका में भी यही तथ्य बताया गया है कि अलग अलग विद्युत वितरण निगमो के साथ हुए अनुबंधनो के चलते मामला पेचीदा है। इसमें करीबन 50 हजार दस्तावेज तथ्यों के तौर पर दायर करे गए है । जिसकी सुनवाई शीघ्र करना अत्यंत ही कठिन है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की ओर से कहा गया कि ट्रिब्यूनल अपनी सुनवाई कैसे करता है यह हाई कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता और न ही यह आदेश पारित कर सकता है कि सुनवाई कर रहे न्यायधीश कैसे और कितनी फीस लेंगे। कानूनन यह दोनों मध्यस्थता में भाग ले रहे पक्षों के बीच ही तय कर जाता है कि मध्यस्थता कर रहे आर्बिट्रेटर की फीस क्या होगी, इसमें अदालतों का हस्तक्षेप उचित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा इसपर भी आपत्ति जताई गई कि हाई कोर्ट इतने पेचीदा मामले की सुनवाई में लग रहे उचित समय को आलसी और अनौपचारिक रवैये के तौर पर बताकर अनुचित करार दे।

किसानों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शांतिपूर्ण रहेगी। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाना है।

'हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होती है। इससे मरीजों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अस्पताल का कितना बिल वास्तव में उनकी बीमा कंपनी चुकाएगी। इलाज की लागत और बीमा दावों को लेकर अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच विवाद होने पर भुगतान में और देरी हो सकती है।

एक प्रस्ताव यह है कि अस्पतालों और बीमा कंपनियों की सहमति से इलाज की बैंचमार्क रेट तय की जाएं। इसका उद्देश्य इलाज की कीमतों को अधिक निश्चित बनाना, विवाद कम करना और फर्ज़ी या अनुचित दावों पर रोक लगाने में मदद करना है।

हालांकि, स्टैण्डर्ड रेट का मतलब यह नहीं होगा कि सभी अस्पतालों में इलाज की कीमत एक जैसी होगी। लोकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टाफिंग, टैक्नोलॉजी और स्पैशलाइज़्ड केयर के स्तर के अनुसार खर्च अलग-अलग होता है। इसलिए, किसी भी बैंचमार्क में ऐसे अंतर को ध्यान में रखना होगा और साथ ही कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर को रोकना होगा।

सुधार की यह पहल तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के बीच हो रही है। चर्चा से जुड़े लोगों के अनुसार, उद्योग के अनुमान में चिकित्सा महंगाई सालाना लगभग 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत है।

अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, दवाइयों, जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस बढ़ने का मतलब है कि बीमा पॉलिसी लेने वालों को अब अपनी जेब से होने वाले खर्च से बचने के लिए ज्यादा इंश्योरैंस कवर की जरुरत पड़ रही है। अगर चिकित्सा खर्च इसी गति से बढ़ता रहा, तो जो बीमा पॉलिसी आज पर्याप्त लगती है, वह कुछ साल बाद उतनी सुरक्षा नहीं दे पाएगी।

विचाराधीन एक अन्य प्रस्ताव, एक समान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का है, जिसे बीमा कंपनियां अपनी मौजूदा पॉलिसियों के साथ पेश करेंगी। इसमें कवरेज, लाभ और शर्तों का एक स्टैण्डर्ड आधार तय किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को अलग-अलग पॉलिसियों की तुलना करना आसान हो जाएगा। इससे जुड़ा एक अन्य प्रस्ताव बीमा के तहत आने वाले इलाज की एक समान सूची तैयार करना है। ऐसी सूची से यह अनिश्चितता कम हो सकती है कि किसी खास इलाज के लिए बीमा मिलेगा या नहीं। इससे बीमा लेने वालों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच विवाद भी कम हो सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए इसका महत्व काफी बड़ा हो सकता है। अलग-अलग पॉलिसियों के जटिल दस्तावेजों, अलग-अलग शर्तों और किन चीजों को शामिल नहीं किया गया है, इसकी तुलना करने के बजाय उनके पास पॉलिसियों को परखने के लिए एक स्पष्ट स्टैण्डर्ड आधार होगा। इन सुधारों का उद्देश्य ऐसे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाना भी है, जहां इलाज का खर्च परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकता है।

भारत में बीमा पर होने वाला खर्च जी.डी.पी. का 4 प्रतिशत से भी कम है, जबकि वैश्विक औसत 7 प्रतिशत से अधिक है। स्वास्थ्य बीमा बाजार में 40 से अधिक बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में उद्योग का प्रीमियम करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये था।

बेहतर स्टैंडर्डाइज़ेशन से पॉलिसी को समझना और उनकी तुलना करना आसान हो सकता है, जिससे कवरेज का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

इन सुधारों की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि वे उपभोक्ताओं की सुरक्षा और हैल्थकेयर सर्विस देने की इकोनॉमिक्स के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। अस्पताल ऐसी तय दरों का विरोध कर सकते हैं जो विशेषज्ञ इलाज की वास्तविक लागत को ध्यान में नहीं रखती हों। वहीं, बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टैंडर्डाइज़ेशन के कारण जरूरी इलाज तक पहुंच सीमित न हो।

बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए सबसे अहम सवाल सीधा है: पॉलिसी में क्या-क्या शामिल होगा, इसकी कीमत कितनी होगी और उन्हें अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा?

अगर प्रस्तावित बदलाव इन सवालों के स्पष्ट जवाब दे पाते हैं, तो वे भारत के स्वास्थ्य बीमा बाजार में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब बढ़ता इलाज का खर्च पर्याप्त बीमा सुरक्षा की जरूरत को लगातार बढ़ा रहा है।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-22820427
आवेदन के लिए क्यूआर स्कैन करें

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगी (ग्राहक सहायता और विक्रय) की भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में नियमित आधार पर कनिष्ठ सहयोगी (ग्राहक सहायता और विक्रय) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

रिक्तियों की संख्या :
नियमित: 7680 + बैकलॉग: 287

पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षणिक योग्यता, आदि), आवश्यक शुल्क, ऑनलाइन आवेदन करने एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए बैंक की वेबसाइट **https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings** पर विज्ञापन क्र. **CRPD/CR/2026-27/17** के अंतर्गत लिंक उपलब्ध हैं. प्रत्याशियों को परामर्श दिया जाता है कि वे विस्तृत विज्ञापन देखें और आवेदन करने एवं शुल्क भुगतान करने से पहले अपने पात्रता मानदंडों और अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें.

- **ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क के भुगतान की तिथि: 11.08.2026 से 31.08.2026 तक.**

अधिक जानकारी के लिए **"CONTACT US" → "Post Your Query"** लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो ऊपर उल्लिखित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings** पर उपलब्ध है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 11.08.2026
महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएम)

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908